Result Mitra

रिजल्ट मित्र स्पेशल

Hand Written

करंट अफेयर्स नोट्स

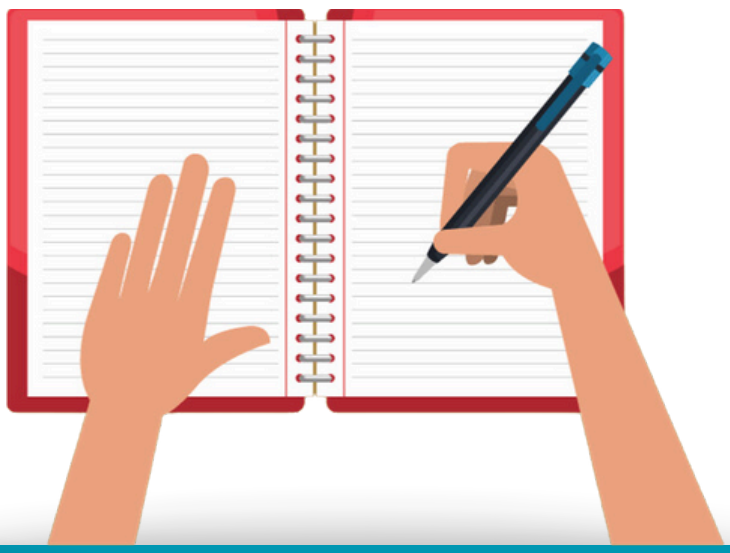

राष्ट्रीय किसान दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत के किसानों और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के योगदान का सम्मान करता है। जो कृषि और ग्रामीण विकास के पक्षधर थे।

2023-24 में कुल 332.2 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष के 329.7 मिलियन टन को पार कर गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

योजना की शुरुआत - 1 दिसम्बर 2018

लाभ - पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता 2000 रुपये की तीन किस्तों में DBT के माध्यम से

नोडल मंत्रालय - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

उद्देश्य

- किसानों की वित्तीय जरूरतें पूरी करना
- फसल स्वास्थ्य और उत्पादन सुधार के लिए मदद
- छोटे जोतों के लिए आर्थिक सहारा
- 100% केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित

Result Mitra

राष्ट्रीय किसान दिवस

चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत के किसानों का नेता और "किसान प्रधानमंत्री" कहा जाता है, ने भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार और नीतियां किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने पर केंद्रित थीं।

मुख्य योगदान:

1. किसानों के अधिकारों की वकालत
2. जमींदारी प्रथा का अंत
3. भूमि सुधार और छोटे किसानों का समर्थन
4. किसानों के लिए कर्ज राहत
5. कृषि आधारित नीतियां
6. भारत का ग्रामीण पुनर्निर्माण" की परिकल्पना
7. सामाजिक और आर्थिक न्याय |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना 2016 में शुरू की गई थी।

- वन नेशन- वन स्कीम थीम पर आधारित
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित किया।

उद्देश्य

प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से फसल नुकसान होने पर बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- किसानों की आय स्थिर करना
- आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं

प्रीमियम दर:- खरीफ फसलों के लिए 2% रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5%

@resultmitra www.resultmitra.com

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)

- छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई।
- यह योजना किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन देती है
- 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55-200 रुपये अंशदान करना होगा।

-18-40 वर्ष आयु वर्ग के किसान

ब्याज सहायता योजना

- केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
- 100% केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित
- 2006-07 में शुरू
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से 3 लाख तक का ऋण 9% की दर से

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- 1998 में शुरू
- NABARD द्वारा विकसित
- 3 लाख तक का ऋण
- वैधता - 5 वर्ष

कृषि अवसंरचना निधि योजना

- 2020 में शुरू की गई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
- अवधि - वित्त वर्ष 2020 से 2032 (वर्ष-10)
- 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% वार्षिक ब्याज अनुदान (7 वर्षों तक)

नमो ड्रोन दीदी योजना

- 2024-25 से 2025-26 के लिए 1261 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृत
- 3 दिसंबर 2024 तक किसान ड्रोन प्रमोशन के लिए 141.41 करोड़ जारी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- 2015 में शुरू की गई।
- अभी तक 24.60 करोड़ कार्ड जारी।
-

किसान कवच

- 17 दिसंबर 2024 को किसान कवच एंटी पेस्टिसाइड बॉडीसूट लॉन्च
- किसानों को सुरक्षा उपकरण वितरित किये

भारत कुवैत संबंध

हाल ही में नरेन्द्र मोदी का कुवैत दौरा जो 52 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

कुवैत के बारे में

- कुवैत अरब प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित एक छोटा लेकिन समृद्ध देश है।
- कुवैत ने 1961 में ब्रिटिश संरक्षण से स्वतंत्रता प्राप्त की।
- 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में वैध मुद्रा था।
- 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान कुवैत ने भारत का समर्थन किया।
- कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा क्रूड तेल आपूर्तिकर्ता है। जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का 3% पूरा करता है।
- प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा 52 वर्षों में पहला था। इससे पहले इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था।
- इसी दौरान कुवैत ने मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर से सम्मानित किया।

@resultmitra www.resultmitra.com

भारत-कुवैत संबंध (India-Kuwait Relations)

1. व्यापार:
o कुवैत भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है।
o भारत कुवैत को मुख्य रूप से चावल, मसाले, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फार्मास्युटिकल उत्पाद निर्यात करता है।
o कुवैत से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक आयात करता है।
2. निवेश:
o कुवैत का सॉवरेन वेल्थ फंड भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करता है।
o भारतीय कंपनियां कुवैत के इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

प्रवासी भारतीय समुदाय:

- कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कुवैत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- भारतीय प्रवासी कुवैत के स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, और सेवा क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- भारतीय समुदाय ने कुवैत की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Result Mitra

सांस्कृतिक संबंध:

- भारत और कुवैत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं।
- भारतीय भोजन, संगीत, फिल्में और त्योहार कुवैत में काफी लोकप्रिय हैं।
- दोनों देश सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

चर्चा में

हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मिशन गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष ने घोषणा की कि भारत अगले 2-3 वर्षों में एक क्वांटम उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है जिससे क्वांटम संचार संभव होगा।

मुख्य बिंदु

क्वांटम सैटेलाइट एक संचार उपग्रह होता है जो क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके अपने संकेतों को सुरक्षित करता है।

* राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) - यह 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा नेतृत्व किया गया एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में क्वांटम अनुसंधान और विकास को मजबूत करना है।

* मिशन का उद्देश्य भारत में 2000 किमी तक फैले उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना है जो अन्य देशों तक भी विस्तारित होगा।

* अप्रैल 2023 में केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा 6000 करोड़ रूपये के बजट के साथ स्वीकृत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) 2023 से 2031 तक चलेगा।

@resultmitra www.resultmitra.com

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission - NQM) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी और क्वांटम विज्ञान में देश को अग्रणी बनाना है। यह मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

मुख्य उद्देश्य:

1. क्वांटम प्रौद्योगिकी का विकास: उन्नत क्वांटम कंप्यूटर, सेंसर्स, क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम नेटवर्क जैसे उपकरणों का विकास।
2. सुरक्षित संचार: क्वांटम संचार के माध्यम से डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना।
3. शोध और नवाचार: क्वांटम भौतिकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
4. वैश्विक प्रतिस्पर्धा: भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में शामिल करना।
5. औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग: क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग उद्योग, स्वास्थ्य, रक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में लागू करना।

पी. वी. नरसिम्हा राव

चर्चा में

- हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

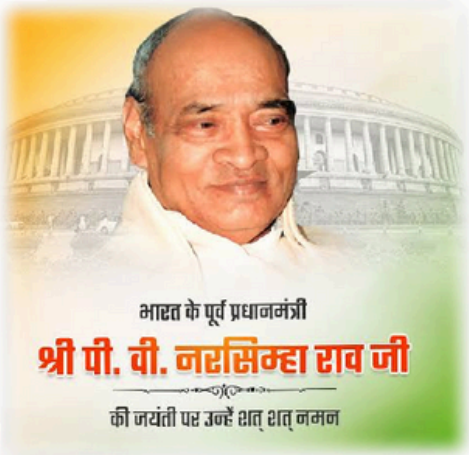

पी. वी नरसिम्हा राव के बारे में

पूरा नाम - पलमपेट वेंकटरमन नरसिम्हा राव

जन्म - 28 जून 1921 (तेलंगाना में)

पद - भारत के 9 वें प्रधानमंत्री (1991-1996)

दल - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

- नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में अग्रसर किया।

नरसिम्हा राव सरकार - प्रमुख विवाद

बाबरी-मस्जिद विध्वंस -

- 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस (सांप्रदायिक दंगे भड़के)

वोट के बदले नकद घोटाला

1993 में कांग्रेस सरकार को विश्वास मत पास कराने के लिए सांसदों की रिश्वत देने का आरोप लगा।

- स्टॉक मार्केट घोटाला
  - 1992 में हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट घोटाले में नरसिम्हा राव पर रिश्वत लेने का आरोप था।

पी. वी. नरसिम्हा राव

पामुलापर्ति वेंकट नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता और देश के नौवें प्रधानमंत्री (1991-1996) थे। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और "आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट" के रूप में जाना जाता है। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए कई बदलावों का साक्षी रहा।

मुख्य योगदान:

- 1. आर्थिक सुधारों की शुरुआत
- 2. विदेशी मुद्रा संकट का समाधान:
- 3. विदेश नीति में सुधार
- 4. उनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992) जैसी घटनाएं हुईं, जिसने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया।

हमारे यहाँ चलने वाली टेस्ट सीरीज की लिस्ट और 1 साल के लिए उनकी Fee निम्न प्रकार है.